



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

५८-११-९८

सं. 232]
No. 232]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 1998/आषाढ़ 4, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 1998/ASADHA 4, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्र एक्सेप्टर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1998

सा.का.नि. 357(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्रन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कलकत्ता पत्रन न्यास कर्मचारी (अशंदायी भविष्य निधि) विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्रन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता पत्रन न्यास का न्यासी मण्डल एतद्वारा कलकत्ता पत्रन कर्मचारी (अशंदायी भविष्य निधि) विनियम में पुनःसंशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस विनियम को कलकत्ता पत्रन न्यास कर्मचारी (अशंदायी भविष्य निधि) विनियम में पुनःसंशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम, 1998 कहा जाएगा।
2. यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
3. कलकत्ता पत्रन न्यास कर्मचारी (अशंदायी भविष्य निधि) विनियम, 1998 के अंतर्गत :—
 - (क) विनियम 14 के खंड (1) और (2) में उल्लिखित शब्द “एक-बारहवां” को “एक-दसवां” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ख) विनियम 16 के खंड (1) में “15 प्रतिशत” शब्द को “12/1/2 प्रतिशत” तथा “प्रतिमाह रु. बेतन को” शब्दों के बीज में समाविष्ट किया जाएगा।
 - (ग) विनियम 19 के उपखंड 7 (iii) शब्द “1/12वां” तथा “1/24वां” में को क्रमशः “1/10वां” तथा “1/20वां” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (घ) विनियम 20 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विनियम 20 : अंशदाताओं को अग्रिम

बरिष्ठ लेखा अधिकारी किसी भी अंशदाता को वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के अनुमोदन से वह राशि जो तीन महीन की बेतन राशि अथवा उसके निधि में जमा बचत राशि का आधी राशि जो भी कम हो को निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए प्रदान कर सकता है।

- (क) अंशदाता तथा उसके पारिवारिक सदस्यों अथवा उस पर आस्तविक आश्रित व्यक्ति की बीमारी, प्रसूति समय या अक्षमता पर, यथावश्यक यात्रा खर्च सहित, होने वाले खर्चों के भुगतान के लिए,

- (ख) अंशदाता तथा उसके पारिवारिक सदस्यों अथवा उस पर वास्तविक आश्रित व्यक्ति के उच्च शिक्षा पर, यथावश्यक यात्रा खर्च सहित होने वाले खर्चों के भुगतान के लिए, निम्नलिखित मामलों में, यथा—
- भारत के बाहर हाई स्कूल स्तर से आगे शैक्षिक, तकनीकी, पेशागत अथवा व्यवसायिक शिक्षा के लिए,
 - भारत में हाई स्कूल स्तर से आगे मैडिकल, इंजिनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते वह पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम का न हो,
- (ग) अंशदाता के वास्तविक स्थिति के प्रथागत अवसरों पर होने वाले आवश्यक खर्चों यथा सगाई या विवाह के उत्सवों, और्येच्छि या अन्य अवसरों पर खर्चों के भुगतान के लिए,
- (घ) अंशदाता तथा उसके पारिवारिक सदस्यों अथवा उस पर वास्तविक आश्रित व्यक्ति के द्वारा अथवा विरुद्ध होने वाले विधिक कार्यवाही पर खर्चों के भुगतान के लिए, इस मामले में अग्रिम अन्य किसी सरकारी श्रोतों द्वारा उक्त मामले के लिए प्राप्त अग्रिम के अतिरिक्त देय होगा।
- (ङ) अंशदाता के बचाव पर होने वाले खर्चों के भुगतान के लिए जहाँ अंशदाता अपने ऊपर लगे किसी सरकारी कदाचार के आरोप की जांच में अपने बचाव के लिए विधि-कर्ता को नियुक्त करता है।
- (च) उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु यथा टी बी, बीसीआर/बी सी पी, बासिंग मशीन, कुकिंग रेज, गेसर्स, कम्प्यूटर इत्यादि।

टिप्पणी—1 इस विनियम के उद्देश्य के लिए वेतन में जहाँ देय हो, महंगाई वेतन शामिल है।

टिप्पणी—2 उस मामले में जांच अंशदाता निर्लिखित रहता है तथा वेतन के स्थान पर निवाह भत्ता प्राप्त करता है, यदि वह अस्थायी अग्रिम के लिए आवेदन करता है, तो इस विनियम के उद्देश्य के लिए “वेतन” वह होगा जो वह अपने निलंबन के शीब्र पहले प्राप्त किया हो।

टिप्पणी—3 जब अंशदाता को इस विनियम के अंतर्गत पहले ही अग्रिम प्रदान किया जा चुका हो उसे इस विनियम के तहत पुनः अग्रिम प्रदान किया जा सकता है, यद्यपि वह पूर्व अग्रिम पूरा का पूरा भुगतान नहीं किया है, फिर भी वैर भुगतान पूर्व अग्रिम को परवर्ती अग्रिम से घटाए जाने का प्रावधान है।

टिप्पणी—4 अध्यक्ष, अंशदाता को विशेष परिस्थिति में अग्रिम भुगतान का अनुमोदन कर सकता है, यदि वह आश्वस्त हो कि संबंधित अंशदाता को विनियम 20 में वर्णित कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।

- (ङ) विनियम 23 निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

विनियम—23 : अप्रत्यार्पणीय निकासी

अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के अनुमोदन से अंशदाता को किसी भी समय निकासी प्रदान की जा सकेगी :—

- (क) अंशदाता की सेवा के 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् (खंडित सेवा अवधि सहित, यदि कोई हो) या उसके अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्ति तिथि के दस वर्ष पूर्व के अन्दर जो भी पहले हो, निधि में जमा बकाया राशि में से निम्नलिखित एक या एकाधिक उद्देश्यों के लिए यथा :—
- (क) अंशदाता अथवा अंशदाता के किसी संतान के उच्च शिक्षा पर, यथावश्यक यात्रा खर्च सहित, होने वाले खर्च के भुगतान के लिए, निम्नलिखित मामलों में, यथा—

- भारत के बाहर हाई स्कूल स्तर से आगे शैक्षिक, तकनीकी, पेशागत अथवा व्यवसायिक शिक्षा के लिए, तथा
- भारत में हाई स्कूल स्तर से आगे मैडिकल, इंजिनियरिंग अथवा अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए,

- (ख) अंशदाता या उसके पुत्रों या उसकी पुत्रियों तथा कोई अन्य उस पर वास्तविक आश्रित स्त्री-संबंधी के सगाई/विवाह संबंधी खर्च के भुगतान के लिए,

- (ग) अंशदाता तथा उसके पारिवारिक सदस्य अथवा उस पर वास्तविक आश्रित व्यक्ति की बीमारी पर, यथावश्यक यात्रा खर्च सहित, होने वाले खर्चों के भुगतान के लिए,

- (घ) उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु यथा टीवी, बीसीआर/बीसीपी, बासिंग मशीन, कुकिंग रेज, गैसर्स, कम्प्यूटर इत्यादि।

- (ङ) अंशदाता के सेवा के दौरान उसके निधि में जमा बाकी राशि निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए यथा—

- (क) भवन या उपयुक्त गृह की प्राप्ति या भूखंड “लागत” सहित बना-बनाया फ्लैट या स्टेट हाउसिंग बोर्ड या हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी के द्वारा भूखंड या फ्लैट के वितरण के मद में किया गया भुगतान।

- (ख) आवास के लिए भवन या उपयुक्त गृह की प्राप्ति या बना-बनाया आवासीय फ्लैट के मद में लिए गये ऋण के बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए,

- (ग) अपने आवास के लिए ए गृह स्थान की खरीद तथा उस पर गृह निर्माण अथवा स्पष्ट रूप से इस हेतु लिए गये ऋण की बकाया राशि को चुकता करने के लिए,

- (घ) अंशदाता का निजी अथवा पहले से ही प्राप्त किया गया मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण, योग्य या परिवर्तन के लिए,

- (ङ) पैतृक मकान या ऋण लेकर बनाया गया गृह के मरम्मत, योग्य या परिवर्तन या रख-रखाव के लिए,

- (च) खंड (ग) के अंतर्गत खरीदे गये गृह स्थान पर गृह निर्माण के लिए,

- (ग) बिना किसी उद्देश्य से संबंधित, निधि में संचित बाकी राशि से अंशदाता के सेवानिवृत्ति या अधिवार्षिता की तिथि के 12 महीने पहले।

टिप्पणी—1 उपखंड (क), (घ), (ड) या (च) या खंड के अंतर्गत निकासी को अनुमोदन के लिए अंशदाता को उस क्षेत्र के नगर पालिका का समूचित अनुमोदित प्लान प्रेषित करना होगा, जिस क्षेत्र में गृह स्थान स्थित है तथा जिसपर निर्माण किया जाना हो अथवा योग या परिवर्तन किया जाना है।

टिप्पणी—2 खंड (ख) उपखंड (ख) अंतर्गत निकासी की अनुमोदित राशि आवेदन तिथि को उपखंड (ख) के अंतर्गत पूर्ववर्ती निकासी सहित, बचत के 3/4 से अधिक नहीं होगी, पूर्ववर्ती निकासी की राशि घटती जाएगी।

सूत्र का अनुसरण इस प्रकार होगा—3/4 का (आवेदित तिथि को बचत—पूर्ववर्ती निकासियों की राशि (गृह निर्माण हेतु) ऋण पूर्ववर्ती निकासी/निकासिया।

टिप्पणी—3 खंड (ख) के उपखंड (क) या (ख) के अंतर्गत निकासी की अनुमति तभी दी जाएगी जब गृह-स्थान या गृह पल्नी या पति के नाम से हो, वह अंशदाता द्वारा भविष्यन्ति राशि प्राप्त करने के लिए प्रथम नामपद किया गया हो।

टिप्पणी—4 इस विनियम के अंतर्गत एक उद्देश्य के लिए मात्र एक निकासी की अनुमति दी जाएगी। एक उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न संतान के लिए विवाह या शिक्षा या विभिन्न अवसरों पर अस्वस्थता अथवा क्षेत्रीय नगर निगम के नवीन अनुमोदित प्लान के द्वारा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गृह या फ्लैट के पुनःवृद्धि या परिवर्तन, शामिल नहीं होगा। उक्त मकान के निर्माण को पूरा करने हेतु खंड (ख) के उपखंड (क) या (च) के अंतर्गत परवर्ती या द्वितीय निकासी, की सीमा टिप्पणी—2 में दिए गए सीमा तक होगी।

टिप्पणी—5 यदि विनियम 20 के अंतर्गत उक्त उद्देश्य के लिए एक ही समय में कोई अग्रिम अनुमोदित किया जा रहा, तो इस विनियम के अंतर्गत निकासी अनुमोदित नहीं होगी।

अप्रत्यपणीय निकासी की शर्तें

- विनियम 23 में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के लिए अंशदाता द्वारा किसी एक समय में राशि की निकासी खंड (क) के अंतर्गत उसके निधि में जमा आकी राशि का 75% से अधिक नहीं होगा तथा विनियम 23 के खंड (ख) के अंतर्गत निकासी के मामलों में उसके निधि में जमा बचत का 90% होगा।
- विनियम 23 ग के अंतर्गत अंशदाता के निधि में जमा आकी राशि का 90% से अधिक का निकासी देय नहीं होगा।
- विनियम 23 के अंतर्गत, किसी अंशदाता को निधि से राशि की निकासी का अनुमति प्राप्त हुआ हो, तो उसे खंड (क) के अंतर्गत निकासी के मामले में 3 महीने के भीतर तथा खंड (ख) के अंतर्गत निकासी के मामले में 6 महीने के भीतर अनुमोदित प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा, कि निकासी की राशि उस पद में ही उपयोग की गई है जिसके लिए निकासी गई थी अथवा गृह का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और यदि ऐसा नहीं होगा, तो निकासी गई सम्पूर्ण राशि उस पर खर्च की गई है, जिसके लिए आवेदन नहीं की गई थी, अंशदाता द्वारा निधि में वह राशि तुरंत एक मुश्त पुनर्भुगतान की जाएगी और यदि ऐसा नहीं होता है तो अंशदाता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
- किसी अंशदाता को विनियम 23 का खंड (ख) का उपखंड (ख) या उपखंड (ग) के अंतर्गत उसके निधि के संचित आकी राशि से राशि-निकासी की अनुमति दी गई हो, वह इस प्रकार निकासी गए राशि से प्राप्त गृह या अन्य प्रकार गृह-स्थान का कोई हिस्सा यदि बेचता है, बंधक (कलकत्ता पत्तन के प्राधिकारी के अतिरिक्त) रखता है, उपहार या अदल-बदल या अन्य प्रकार का कार्य अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकता।

निष्पलिखित के लिए उक्त अनुमति का प्रावधान आवश्यक नहीं है।

- अधिक से अधिक तीन वर्ष के लिए गृह या गृह-स्थान का पट्टा दिए जाने के लिए, या
- केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित या के अधीन हाऊसिंग बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा निगम या अन्य निगम जो नए गृह निर्माण अथवा वर्तमान गृह के पुनःवृद्धि, परिवर्तन, के लिए अग्रिम, ऋण देता है, की बंधक रखे जाने के लिए।
- अंशदाता को प्रति वर्ष 31 दिसंबर के पूर्व यह ओषित करना होगा कि गृह या गृह-स्थान, जो भी हो, लगातार उसके कहने में रहेगा अथवा बंधक या हस्तांतरण या छोड़े जाने के अवस्था में, यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो अनुमोदन प्राधिकारी के सम्मुख उसके द्वारा इस हेतु निर्दिष्ट तिथि को या उसके पूर्व प्रस्तुत करना होगा, मूल विक्रय, बंधक या पट्टा विलेख तथा वह दस्तावेज जिसपर सम्पत्ति का अधिकार आधारित हो।
- यदि अंशदाता अपने सेवा-निवृत्ति के पूर्व किसी भी समय कब्जे के गृह या गृह-स्थान को अनुमति प्राधिकारी के बिना किसी पूर्व अनुमति के कब्जे को खारिज करता है, तो उसके द्वारा निकासी गई राशि को एक मुश्त रूप से निधि में तुरंत पुनर्भुगतान करना होगा और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो अंशदाता पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जा सकता है। निकासी के लिए विस्तृत कार्यवाही, अंशदाता भविष्य निधि विनियम के विनियम 23 (ख) का विस्तार परिशिष्ट 1 में है।

विनियम 24 तथा विनियम 24(2) को निरस्त किया जाएगा

[सं. पी. आर. 12016/7/98-पी. ई.-I]

के. वी. राष्ट्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी—कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (अंशदाती भविष्य निधि) विनियम, 1988, का प्रकाशन भारत के राजपत्र में जी. एस. आर. सं. 637(ई) दिनांक 23 मई, 1988 के अंतर्गत हुआ था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1998

G.S.R. 357(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Contributory Provident Fund) Regulations, 1998 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Calcutta Port Trust hereby make the following regulations further to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Contributory Provident Fund) Regulations :—

1. **Short Title.**—These Regulation may be called Calcutta Port Trust Employees' (Contributory Provident Fund) 1st Amendment Regulations, 1998.
2. This will come into force from the date of publication in the Official Gazette.
3. In the Calcutta Port Trust Employees' (Contributory Provident Fund) Regulations, 1998:—
 - (a) In Regulation 14 the word "one-twelfth" appearing in Clauses (1) and (2) shall be substituted by the word "one-tenth".
 - (b) In Regulation 16 the words "15 per cent" may be incorporated between the words "12½ per cent" and "of pay per month.....rupee" appearing in clause (1).
 - (c) In Regulation 19, sub-clause 7(iii) the words "1/12th" and "1/24th" will be substituted by the words "1/10" and "1/20th" respectively.
 - (d) Regulation 20 shall be substituted by the following:—

Regulation 20: Advances to Subscribers.

The Senior Accounts Officer may, with the approval of Financial Adviser and Chief Accounts Officer grant advance to any subscriber a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes:—

- (a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;
- (b) to meet cost of higher education, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely:—
 - (i) for education outside India for academic technical professional or vocational course beyond the High School stage and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years;
- (c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;
- (d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source.
- (e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.
- (f) to purchase consumer durables such as TV, VCR/VCP, washing machines, cooking range, geysers, computers etc.

Note 1. For the purpose of this regulation pay includes dearness pay where admissible.

- Note 2.** In the case of a subscriber who applies for a temporary advance while he is under suspension and draws subsistence allowance instead of pay, the 'pay' for the purpose of this regulation shall be that which he drew immediately before he was placed under suspension.
- Note 3.** When an advance has already been granted to a subscriber under this regulation, a subsequent advance may be granted to him/her under this Regulation even though the previous advance may not have been repaid in full, provided, however, that the unpaid balance of the previous advance shall be deducted from the advance subsequently granted.
- Note 4.** The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned under Regulation 20.

(e) Regulation 23 shall be substituted by the following :—

Regulation 23 : Non refundable withdrawals

Subject to the sanction of the Chairman or Deputy Chairman withdrawals may be granted to a subscriber at any time—

- (A) After the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement or superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely—
- (a) meeting the cost of higher education, including, where necessary the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely—
 - (i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage ; and
 - (ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;
 - (b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber of his sons or his daughters, and any other female relation actually dependent on him ;
 - (c) meeting the expenses in connection with the illness, including, where necessary, the travelling expenses of the subscriber and member of his family or any person actually dependent on him ;
 - (d) meeting the cost of consumer durables such as TV, VCR/VCP, washing machines, cooking range, geysers, computers, etc.
- (B) During the service of a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely—
- (a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by State Housing Board or a House Building society.
 - (b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence ;
 - (c) Purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose ;
 - (d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;
 - (e) renovating, additions or alterations or upkeep of the ancestral house or a house built with the assistance or loan ;
 - (f) constructing a house on a site purchased under Clause (c).
- (C) Within twelve months before the date of subscriber's retirement or superannuation from the amount standing to the credit in the fund, without linking to any purpose.

Note—1 Withdrawal under sub-clause (a), (d), (e) or (f) or Clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

Note—2 The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of Clause (B) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (b), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is 3/4th of the balance as

1766 21.10.82

on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal(s).

- Note—3 Withdrawal under sub-clause (a) or (b) of Clause (B) shall also be allowed where the house-site or house is in the name of wife or husband provided he or she is the first nominee to receive Provident fund money in the nomination made by the subscriber.
- Note—4 Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of Clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under Note—2.
- Note—5 A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under Regulation 20 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

Conditions for non-refundable withdrawal :

(I) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in Regulation 23 shall not exceed 75% of the balance at his credit in the fund in case of withdrawals under Clause (A) and 90% of the balance at his credit in the fund in case of withdrawals under Clause (B) of Regulation 23.

(II) The Withdrawal admissible under Regulation 23C shall not exceed 90% of the amount standing to the credit of the subscriber in the fund.

(III) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the fund under Regulation 23 shall satisfy the sanctioning authority within a period of 3 months in case of withdrawals under Clause (A) and 6 months in case of withdrawals under Clause (B) that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn or the construction of the house has been commenced and if he fails to do so the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, the subscriber will be liable for disciplinary action.

(IV) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a) or sub-clause (b) or sub-clause (c) of Clause (B) of Regulation 23 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchase with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Calcutta Port Trust Authority), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Sanctioning Authority:

Provided that such permission shall not be necessary for—

- (i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or
- (ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances, loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(V) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged otherwise transferred or let out us aforesaid and shall, if so required, produce before the Sanctioning Authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(VI) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Sanctioning Authority, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lumpsum to the Fund, and in default of such repayment, the subscriber shall be liable for disciplinary action. The detailed procedure for withdrawal under Regulation 23 (B) is annexed as Appendix-I of Contributory Provident Fund Regulation.

(e) Regulation 24 and Regulation 24(2) shall be deleted.

[F. No. PR-12016/7/98-PEI]

K. V. RAO, Jt. Secy.

Note. The Calcutta Port Trust Employees' (Contributory Provident Fund) Regulations, 1988 were published vide G.S.R. No. 637(E) dated 23rd May, 1988 in the Gazette of India.